

मैसर्स. जॉर्ज ओक्स (पी.) लिमिटेड

बनाम

मद्रास राज्य

[एसके दास, जे.एल कपूर, एम. हिदायतुल्ला, जे.सी. शाह, और टीएल

वेंकटरामा अय्यर न्यायाधिपति]

बिक्री कर-कारोबार-यदि विक्रेता द्वारा एकत्र किया गया कर शामिल है- कानून को संवैधानिकता मानना भारत का संविधान, प्रविष्टि 54, सूची II सातवीं अनुसूची-भारत सरकार अधिनियम, 1935 (26 जियो. 5 और 1 संस्करण. 8 अध्याय 2), प्रविष्टि 48, सूची 11, एसएच. VII-मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, (1939 का अधिनियम IX), एस.एस. 2(i), 2(h), 8 बीमद्रास जनरल सेल्स (परिभाषा)। टर्नओवर और मूल्यांकन का सत्यापन) अधिनियम, 1954 (मैड)। XVII 1954), एस.एस. 2, 3-कारोबार और मूल्यांकन नियम, आरआर। 4, 5, 6, 11.

अपीलकर्ताओं द्वारा बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई कुछ राशियाँ बिक्री कर द्वारा उनके टर्नओवर में शामिल किया गया था अधिकारी। उन्होंने की संवैधानिक वैधता का विरोध किया मद्रास जनरल सेल्स (टर्नओवर की परिभाषा और) मूल्यांकन का सत्यापन) अधिनियम, 1954, जमीनी स्तर पर अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कि राज्य विधानमंडल अपनी विधायिका से आगे निकल गया संविधान की सूची की प्रविष्टि 54

के तहत योग्यता आक्षेपित अधिनियम द्वारा यह अधिनियमित किया गया कि एकत्र की गई राशियाँ कर के माध्यम से डीलर का हिस्सा माना जाएगा उसके टर्नओवर का.

यह निर्धारित किया गया कि सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 संविधान अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 48 के समान है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बिक्री माल को स्वामित्व प्रदान करने वाला लेनदेन माना गया है विक्रेता से क्रेता तक और वह मात्र निष्पादक उस प्रविष्टि के अर्थ में समझौता बिक्री नहीं था। प्रविष्टि 54 को भी यही अर्थ दिया जाना चाहिए।

मद्रास राज्य बनाम गैनन इंकरली एंड कंपनी, लिमिटेड , [1959] एससीआर 379 और बिक्री कर अधिकारी बनाम मैसर्स. बुध प्रकाश जयप्रकाश, [1955] 1 एससीआर 243, संदर्भित।

मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट के धारा 2(i) और 2(h), 1939, के तहत अभिव्यक्ति "टर्नओवर" का अर्थ कुल राशि है जिसके लिए सामान या तो नकद या आस्थगित भुगतान पर बेचा जाता है या अन्य मूल्यवान प्रतिफल, और जब कोई बिक्री आकर्षित करती है क्रय कर जो उपभोक्ता को दिया जाता है खरीदार को जो भुगतान करना होगा उसमें कर और कुल राशि शामिल है भुगतान किया जाना टर्नओवर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। जब विक्रेता कर देता है और खरीदार सहमत होता है कीमत के

अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान करें, कर वास्तव में है हकदारी संबंधी विचारों का भाग।

पप्रेका लिमिटेड बनाम व्यापार मंडल, [1944] 1 सभी ईआर 372, लव वी. नॉर्मन राइट (बिल्डर्स) लिमिटेड, [1944] 1 सभी ईआर 618, पालन किया।

अशोक मार्केटिंग कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, [1959] आईओ एसटीसी 110 और टाटा आयरन एंड स्टील कं. बनाम बिहार राज्य, [1958] एससीआर 1355, संदर्भित।

हालाँकि एस. मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 की धारा 8 बी और टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों में अलग से उल्लेख किया गया है ऐसे भुगतान के उद्देश्य से कर के रूप में एकत्र की गई राशि सरकार के बराबर, कोई अपरिवर्तनीय भेद नहीं था बिक्री मूल्य और कर के बीच कोई अंतर नहीं था आक्षेपित अधिनियम की धारा 2 के तहत भेद बनाए रखा गया। यह मानते हुए कि विधायिका में ऐसा भेद मौजूद था की सूची II में प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम था संविधान में कहा गया है कि कर का गठन माना जाएगा टर्नओवर का हिस्सा और के लिए भेद मिटाना सीमित अवधि जिसके दौरान विवादित अधिनियम लागू हुआ। इसलिए विवादित अधिनियम वैध था।

वाणिज्यिक कर उपायुक्त बनाम एम. क्विशना - स्वामी मुदलियार,
[1954] 5 एसटीसी 88, लागू नहीं माना गया। श्री सुंदरराजन एंड कंपनी
बनाम मद्रास राज्य, [1956] 7 एसटीसी 105, स्वीकृत।

अन्ध्या सरकार बनाम ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड ,
[1957] 8 एसटीसी 114 और बंगाल इन्स्युनिटी कं लिमिटेड बनाम बिहार
राज्य , [1955] 2 एससीआर 603, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1960 की सिविल अपील संख्या 280
और 281

1956 की टीआरसी संख्या 101 और 102 में मद्रास उच्च न्यायालय
के 20 अप्रैल, 1956 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता के लिए *बी. गणपति अय्यर* और *जी. गोपालकृष्णन*।

प्रतिवादी की ओर से *एमएम इस्माइल* और *टीएम सेन*।

इंटरवेनर नंबर 1 के लिए *डीवी शास्त्री* और *टीएम सेन*, इंटरवेनर
नंबर 2 के लिए *नौनित लाल*।

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 3 के लिए *एसएम सीकरी*, महाधिवक्ता, पंजाब
और *डी. गुप्ता*।

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 4 के लिए *एसएम सीकरी*, महाधिवक्ता, पंजाब,
एनएस बिंद्रा और *डी. गुप्ता*।

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 5 के लिए जीसी कासलीवाल, महाधिवक्ता, राजस्थान, एसके कपूर और डी. गुप्ता।

1961, 28 अप्रैल, को न्यायालय का निर्णय एस.के. दास, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया - यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर दो अपीलें हैं और 22 मार्च, 1957 के उसके आदेशों द्वारा समेकित हैं। वे निर्णय और आदेशों से हैं उक्त उच्च न्यायालय के दिनांक 20 अप्रैल, 1956 और 30 जुलाई, 1956 को दो कर संशोधन मामलों में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा धारा के तहत दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। 12- मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट (1939 का मद्रास एक्ट IX) का बी, जिसे इसके बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में मूल अधिनियम कहा जाएगा।

मेसर्स जॉर्ज ओक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, यहां अपीलकर्ता, फोर्ड मोटर कारों, स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण के डीलर हैं। दो वर्षों 1951-52 और 1952-53 के लिए अपीलकर्ताओं ने मूल अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपने रिटर्न जमा किए और बिक्री के लेनदेन पर प्राप्त कुछ राशि के संबंध में कर से छूट का दावा किया, जिसके बारे में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये अंतर-राज्यीय बिक्री थीं और इसलिए अधिनियम संविधान का 286 जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, के तहत कर से छूट। उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास ने न केवल छूट

के दावे को खारिज कर दिया, बल्कि टर्नओवर में कुछ रकम भी जोड़ दी, जो अपीलकर्ताओं ने कर के रूप में एकत्र की थी। 1951-52 के लिए जोड़ी गई राशियाँ थीं - (ए) रु. 8,000 प्रति रुपये 3 पाई पर मूल्यांकन योग्य शुद्ध कारोबार, और (बी) रु. 9 पाई प्रति रुपये की दर से 4,30,000 टर्नओवर का आकलन किया जाएगा। 1952-53 के लिए जोड़ी गई राशियाँ थीं - (ए) रु. 30,132 विषम और (बी) रु. क्रमशः 2,92,257 विषम।

उप वाणिज्यिक कर अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने विशेष वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील, मद्रास सिटी के समक्ष दो अपीलें दायर कीं। ये अपीलें खारिज कर दी गईं। इसके बाद मामला दो अपीलों के माध्यम से बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण में ले जाया गया। इस समय तक मद्रास विधानमंडल ने मद्रास जनरल सेल्स (टर्नओवर की परिभाषा और आकलन की मान्यता) अधिनियम, 1954 पारित कर दिया था, जो 1954 का मद्रास अधिनियम संख्या XVII था। इस अधिनियम को हम इस निर्णय में विवादित अधिनियम के रूप में संदर्भित करेंगे, क्योंकि यह इन अपीलों में निर्णय के लिए अब संवैधानिक वैधता ही एकमात्र प्रश्न है। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के दावे को इस तर्क से खारिज कर दिया कि प्रासंगिक वर्षों में कुछ बिक्री लेनदेन प्रभावी रूप से अंतरराज्यीय बिक्री थे और इसलिए कर से मुक्त थे; ट्रिब्यूनल ने विवादित अधिनियम की संवैधानिक वैधता के दूसरे प्रश्न पर जाने से इनकार कर दिया। हम यहां बता सकते हैं, हालांकि अब इस पर कुछ भी नहीं कहा

गया है, कि ट्रिब्यूनल ने माना कि जब बिक्री कर को टर्नओवर में शामिल किया गया था, तो मूल अधिनियम की धारा 3(1) के तहत केवल न्यूनतम दर पर शामिल राशि पर कर लगाना उचित था, अर्थात्, रुपये में 3 पाई।

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने धारा के तहत उच्च न्यायालय में दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। मूल अधिनियम की धारा 12-बी इन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले में खारिज कर दिया गया। 20 अप्रैल, 1956 के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने माना कि कुछ लेन-देन अंतर-राज्य बिक्री होने का विवाद उसके पहले के निर्णयों में से एक द्वारा समाप्त किया गया था, जो अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य, 1958 की सिविल अपील संख्या 446 में हमारे सामने आया था। उस अपील में हमने 28 मार्च 1961 को फैसला सुनाया और माना कि बिक्री कर कानून (मान्यता) अधिनियम , 1956 लागू होता है और लेनदेन की वास्तविक प्रकृति पर विचार करना अनावश्यक था, जिसका अपीलकर्ताओं ने अंतरराज्यीय बिक्री होने का तर्क दिया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे सामने स्वीकार किया है कि निर्णय वर्तमान अपीलों को नियंत्रित करता है, और पहला प्रश्न अब जीवित नहीं है।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने गलती से 20 अप्रैल, 1956 के अपने आदेश में इस पर विचार नहीं किया। जब मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो उसने 30 जुलाई, 1956 के अपने

आदेश में कहा कि दूसरा प्रश्न भी श्री सुंदरराजन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य(1) में अपने निर्णय से समाप्त हुआ, जहां लागू अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया था।

जब हमने इन अपीलों को *अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य*, 1958 की सिविल अपील संख्या 446, के साथ सुना, तो हमने विचार व्यक्त किया कि दूसरे प्रश्न और इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर उच्च न्यायालयों में कुछ मतभेद थे। हमारे सामने विचार यह था कि क्या विवादित अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत वैध रूप से बनाया गया था: इस प्रकार उठाया गया प्रश्न विधायी क्षमता में से एक था और सभी राज्यों को प्रभावित करता था। मद्रास राज्य पहले से ही इन अपीलों का प्रतिवादी पक्ष था। तदनुसार, हमने अन्य सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उक्त नोटिस के अनुसरण में आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के महाधिवक्ता हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से मद्रास राज्य के इस कथन का समर्थन किया है कि विवादित अधिनियम वैध है; उनमें से कुछ ने उस निवेदन के समर्थन में पूरक तर्क जोड़े हैं।

सुविधा और संक्षिप्तता के लिए हम इस निर्णय में दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य तर्कों का उल्लेख करेंगे; सबसे

पहले, अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क है कि मूल अधिनियम के कई प्रावधान भी हैं साथ ही विवादित अधिनियम की धारा 2 में बेची गई वस्तुओं की बिक्री कीमत और कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि के बीच अंतर किया गया है और उस अंतर को ध्यान में रखते हुए, विवादित अधिनियम जो लगाना चाहता है वह 'बिक्री-कर पर कर' एक विषय है जो सूची II की प्रविष्टि 54 के दायरे में नहीं आता है, जिसे प्रासंगिक समय में "समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरी ओर, तर्क यह है कि विवादित अधिनियम का उद्देश्य 'टर्नओवर' की परिभाषा के दायरे को बढ़ाना है ताकि टर्नओवर में कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि को एक डीमिंग प्रावधान द्वारा शामिल किया जा सके और इसे राज्य विधानमंडल राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम था। ये दो पक्षों के मुख्य तर्क हैं; लेकिन प्रत्येक पक्ष में मुख्य तर्क के समर्थन में कई सहायक बिंदु हैं, और इन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना अत्यधिक सरलीकरण होगा। इसलिए, प्रत्येक पक्ष के मुख्य तर्क पर विचार करते समय हम उन पर भी विचार करेंगे।

हम सबसे पहले मूल अधिनियम और आक्षेपित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे, जहां तक वे हमारे समक्ष बहस किए गए बिंदुओं पर आधारित हैं। मूल अधिनियम की धारा 3 जो कि चार्जिंग धारा है, के तहत प्रत्येक डीलर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक

वर्ष के लिए अपने कुल कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी गणना ऐसे टर्नओवर के एक विशेष प्रतिशत पर की जाती है। 'टर्नओवर' क्या है इसे धारा 2(i) में परिभाषित किया गया है। परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है- "'टर्नओवर' का मतलब कुल राशि है जिसके लिए सामान या तो डीलर द्वारा खरीदा या बेचा जाता है, चाहे नकद के लिए या स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए... 'बिक्री' को धारा 2(एच) में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है (हम केवल उतनी ही परिभाषा पढ़ रहे हैं जितनी हमारे उद्देश्य के लिए सामग्री है) "नकद या स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान के लिए व्यापार या व्यवसाय के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण विचार।" यहां यह ध्यान देने योग्य है कि मूल अधिनियम द्वारा लगाया गया कर कुल टर्नओवर पर एक कर है, और टर्नओवर का मतलब कुल राशि है जिसके लिए किसी डीलर द्वारा सामान खरीदा या बेचा जाता है। इसलिए, जो प्रश्न आते हैं उनमें से एक विचार के लिए यह है कि क्या राज्य विधानमंडल आक्षेपित अधिनियम को लागू करने में अपनी विधायी क्षमता से परे चला गया है कि कर के माध्यम से डीलर द्वारा एकत्र की गई राशि को उसके कारोबार का हिस्सा माना जाएगा। यह हमें मूलधन की धारा 8 बी पर लाता है अधिनियम, जो उप-धारा (1) में प्रदान करता है की कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत व्यापारी नहीं है, कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा; न ही कोई पंजीकृत डीलर

ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अनुसार, जो निर्धारित किया जा सकता है, को छोड़कर ऐसा कोई संग्रह नहीं करेगा; एवं उप धारा (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कर के रूप में कोई राशि एकत्रित की है, उसे राज्य सरकार को भुगतान करना होगा। धारा 15 मूल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में दंड प्रदान करता है जिसमें धारा 8 बी शामिल है।

वाणिज्यिक कर उपायुक्त, कोयंबटूर डिवीजन बनाम एम. क्रिघनास्वामी मुदलियार एंड संस (2) में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पंजीकृत डीलर द्वारा उपभोक्ता से बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि को बेची गई वस्तुओं की बिक्री मूल्य के हिस्से के रूप में पंजीकृत डीलर के टर्नओवर में शामिल किया जाना चाहिए और इस पर दोबारा कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही सरकार को भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय 7 जनवरी 1954 को दिया गया था। जुलाई 1954 में आक्षेपित अधिनियम धारा 2 और 3 अधिनियमित किया गया था , जिसे केवल यहाँ निर्धारित करने की आवश्यकता है।

"धारा 2. डीलरों द्वारा बिक्री कर संग्रह को टर्नओवर का हिस्सा माना जाएगा - 1 अप्रैल 1954 से पहले एक डीलर द्वारा की गई बिक्री के मामले में, मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1939 के तहत कर के माध्यम से उसके द्वारा एकत्र की गई राशि (1939 का मद्रास अधिनियम

IX) (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), उसके कारोबार का हिस्सा माना जाएगा।

3. कुछ मूल्यांकन और संग्रह का सत्यापन.- (1) किए गए सभी आकलन, और संग्रह, पारित किए गए सभी आदेश, मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार या शक्ति के अभ्यास या कथित अभ्यास में किसी भी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाई, और किसी भी न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा सुनाए गए सभी निर्णय, डिक्री या आदेश मूल अधिनियम में मामलों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र या शक्तियों का प्रयोग, इस आधार पर कि 1 अप्रैल 1954 से पहले मूल अधिनियम के तहत कर के माध्यम से एक डीलर द्वारा एकत्र की गई राशि, जो डीलर के कारोबार का हिस्सा है, को इसके द्वारा घोषित किया जाता है जैसा भी मामला हो, वैध रूप से बनाया, पारित, लिया या सुनाया गया हो; और किसी भी अधिकारी, न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी विपरीत प्रभाव और किसी भी आदेश, निर्णय या डिक्री द्वारा दर्ज किया गया कोई भी निष्कर्ष, जहां तक ऐसा आदेश, निर्णय या डिक्री सन्निहित है या ऐसे किसी निष्कर्ष पर आधारित है और केवल की लागत से संबंधित नहीं है। वह कार्यवाही जिसका परिणाम निर्णय, डिक्री या आदेश के रूप में निकले, शून्य होगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी कार्य या चूक एक अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगी जो इतना दंडनीय नहीं होता यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता।

(2) उप-धारा (1) में किसी भी अधिकारी को मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार या शक्तियों के अभ्यास या कथित अभ्यास के किसी भी डीलर का आकलन करने में, एकत्र की गई राशि को डीलर के कारोबार में शामिल करने के लिए अधिकृत करने के रूप में नहीं माना

जाएगा। 1 अप्रैल 1954 के बाद उनके द्वारा मूल अधिनियम के तहत कर के माध्यम से।"

इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में विवादित अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया गया और श्री सुंदरराजन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य (3) मामले में यह माना गया कि विवादित अधिनियम वैध था। उच्च न्यायालय ने बताया कि कृष्णास्वामी मुदलियार (4) के मामले में पहले का निर्णय यह नहीं था कि राज्य विधानमंडल एक पंजीकृत डीलर द्वारा धारा के तहत कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि का भुगतान नहीं कर सकता है। धारा 8 बी मूल्यांकन योग्य टर्नओवर का हिस्सा है, लेकिन मूल अधिनियम जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, ऐसी रकम को मूल्यांकन योग्य टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनाता था। यह माना गया कि सार और सार में लागू अधिनियम 1 अप्रैल, 1954 से पहले ही किए गए आकलन

को मान्य करता है और यहां तक कि जहां पंजीकृत डीलर ने धारा 8 बी के अधिकार के तहत कर के माध्यम से कोई भी राशि एकत्र की है, क्रेता द्वारा भुगतान डीलर द्वारा बिक्री के अवसर पर किया गया था और बाद की तुलना में यह वास्तव में उस कीमत का हिस्सा था जो क्रेता ने सामान खरीदने के लिए विक्रेता को भुगतान किया था। यही विचार *अशोका मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य* (5) में बिहार बिक्री कर (टर्नओवर की परिभाषा और मूल्यांकन की मान्यता) अधिनियम, 1958 के संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी व्यक्त किया गया था। हमारा सवाल यह है कि क्या उपरोक्त दृष्टिकोण सही है।

प्रासंगिक विधायी प्रविष्टि, जैसा कि हमने पहले कहा है, सूची II की प्रविष्टि 54 है- "समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर।" भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची VII की सूची 11 में एक समान प्रविष्टि (संख्या 48) को, "माल की बिक्री पर कर" के रूप में पढ़ा जाता है। उस प्रविष्टि के वास्तविक दायरे और प्रभाव पर इस न्यायालय ने *मद्रास राज्य बनाम गणनों इंकरले और कं. (मद्रास) लिमिटेड* (6) और आगे के मामले में विचार किया था। इस विषय से संबंधित कई निर्णयों की समीक्षा में यह माना गया कि अभिव्यक्ति "माल की बिक्री" माल की बिक्री से संबंधित सामान्य कानून में और उस विषय से संबंधित विधायी अभ्यास में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कानूनी आयात का एक शब्द था और होना चाहिए माल की बिक्री अधिनियम , 1930 के समान

अर्थ के रूप में व्याख्या की गई; दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की प्रविष्टि 48 द्वारा विचार की गई बिक्री लेनदेन थे जिसमें माल का शीर्षक विक्रेता से पारित हो गया खरीदार, और *सेल्स टैक्स ऑफिसर, पीलीभीत बनाम मेसर्स बुद्ध प्रकाश जय प्रकाश (7)* में यह माना गया था कि केवल निष्पादन समझौता उस प्रविष्टि के अर्थ के भीतर बिक्री नहीं था। हमें लगता है कि वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 54 में है। हमारे सामने सवाल यह है कि प्रविष्टि को वह अर्थ देते हुए, क्या विवादित अधिनियम एक सक्षम विधानमंडल द्वारा वैध कानून का हिस्सा है?

अब, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे सामने यह तर्क नहीं उठाया है कि किसी भी मामले में राज्य विधानमंडल वैध रूप से एक कानून नहीं बना सकता है जिसमें डीलर के कारोबार के हिस्से के रूप में कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनके लिए ऐसे किसी व्यापक प्रस्ताव पर जोर देना अनावश्यक है। उनका तर्क है कि मूल अधिनियम के धारा 8बी, 15 एवं धारा 2 द्वारा, जिसे वह बिक्री मूल्य कहता है और डीलर द्वारा कर के माध्यम से जो एकत्र किया जाता है, उसके बीच अंतर करने के बाद, विवादित अधिनियम की वैधता का प्रश्न उस अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, कि आक्षेपित क्या है अधिनियम का तात्पर्य उस चीज़ को लागू करना है जिसे

विद्वान वकील "कर पर कर" कहते हैं और इसलिए यह प्रासंगिक विधायी प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आता है। उनका आगे कहना है कि कर के माध्यम से जो भी एकत्र किया जाता है वह बिक्री मूल्य और इसलिए टर्नओवर से अलग होता है, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि अनिवार्य रूप से बिक्री के लेन-देन से जुड़ा हुआ है और इसलिए "कर पर कर" लगाने का बिक्री के लेन-देन से कोई आवश्यक संबंध नहीं है जैसा कि माल की बिक्री से संबंधित सामान्य कानून में समझा जाता है।

हम इस तर्क को सही नहीं मान पा रहे हैं। सबसे पहले, हम यह नहीं सोचते हैं कि या तो मूल अधिनियम या आक्षेपित अधिनियम, बिक्री मूल्य और कर के बीच किसी अपरिवर्तनीय अंतर पर आगे बढ़ता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने सुझाव दिया है। मूल अधिनियम में बिक्री मूल्य की कोई अलग परिभाषा नहीं है। हम पहले ही 'बिक्री' और 'टर्नओवर' की परिभाषाओं का उल्लेख कर चुके हैं, वे परिभाषाएँ ऐसा कोई भेद नहीं दर्शाती हैं। इसके विपरीत, अभिव्यक्ति 'टर्नओवर' का मतलब कुल राशि है जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है, चाहे नकद के लिए या स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए, और जब बिक्री पर खरीद कर लगता है और कर उपभोक्ता को दिया जाता है, खरीदार को सामान के लिए जो भुगतान करना होता है उसमें कर भी शामिल होता है और भुगतान की गई कुल राशि टर्नओवर की परिभाषा में आती है।

पैपरिका लिमिटेड और अन्य बनाम व्यापार बोर्ड (8) न्यायाधीश लॉरेंस ने कहा,

"जब भी किसी बिक्री पर खरीद कर लगता है, तो वह कर संभवतः उस कीमत को प्रभावित करता है, जिस पर विक्रेता, जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, मांग करता है, लेकिन यह समाप्त नहीं होता है वह कीमत होगी जो खरीदार को चुकानी होगी, भले ही कीमत x प्लस खरीद कर के रूप में व्यक्त की गई हो।"

वही विचार *लव बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स), लिमिटेड* (9) में फिर से व्यक्त किया गया जब न्यायाधीश गोडार्ड ने कहा:

"जहां किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, चाहे वह खरीद कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क हो, कर उस कीमत का हिस्सा बन जाता है जिसे आम तौर पर खरीदार को भुगतान करना होगा। तंबाकू के एक औंस की कीमत दर के कारण होती है कर का, लेकिन बिक्री पर केवल एक ही प्रतिफल होता है, हालांकि लागत प्लस लाभ प्लस कर से बना होता है। इसलिए, यदि कोई विक्रेता बिक्री के लिए सामान पेश करता है, तो उसे एक कीमत उद्धृत करनी होगी जिसमें कर भी शामिल है यदि वह इसे पास करना

चाहता है खरीदार पर। यदि खरीदार कीमत से सहमत है, तो यह विचार करना उसके लिए नहीं है कि यह कैसे बना है या विक्रेता ने कर शामिल किया है या नहीं।"

हम सोचते हैं कि ये टिप्पणियाँ उन अधिनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में भी उपयुक्त हैं जिन पर हम अभी विचार कर रहे हैं, और उन प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जब डीलर कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, तो वह इसका हिस्सा नहीं हो सकता है विक्रय कीमत। जहां तक क्र्रेता का सवाल है, वह सामान के लिए वही भुगतान करता है जो विक्रेता मांगता है, अर्थात् कीमत, भले ही इसमें कर शामिल हो। यह बिक्री के लिए संपूर्ण प्रतिफल है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्र्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई पूरी राशि को बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है। मूल अधिनियम की धारा 8बी और टर्नओवर और मूल्यांकन नियम की धारा 19 के तहत बनाए गए नियम दर्शाता है कि मूल अधिनियम की योजना के तहत कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि और खरीद मूल्य की राशि के बीच अंतर किया जाता है। यह वास्तव में सत्य है कि धारा 8बी कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि का अलग से उल्लेख किया गया है, और जबकि उप

धारा (1) यह केवल इस अर्थ में सक्षम है कि एक पंजीकृत डीलर कर, उप-धाराओं को पारित कर सकता है। उप धारा (2) पंजीकृत डीलर पर उसके द्वारा एकत्रित कर की राशि सरकार को भुगतान करने का दायित्व लगाया गया है। *कृष्णास्वामी मुदलियार* (10) के मामले में फैसले के निम्नलिखित उद्धरण में टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों के तहत स्थिति को सही ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

"नियम 4 में प्रावधान है कि नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी डीलर का सकल कारोबार वह राशि है जिसके लिए डीलर द्वारा सामान बेचा जाता है। नियम 5 में कुछ कटौतियों और कर लगाने के तरीके या तरीके के लिए प्रावधान किया गया है। लगाए जाने वाले बिंदु पर पहुंचना होगा। इन नियमों का उद्देश्य शुद्ध टर्नओवर का आकलन करना है, जिस पर चार्जिंग अनुभाग के तहत कर लगाया जाना है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चार्जिंग अनुभाग के तहत, कर का भुगतान किया जाना है। टर्नओवर जिसका मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया जाता है। नियम 11 के अनुसार प्रत्येक डीलर को नियम 6 के तहत हर साल फॉर्म ए में कर निर्धारण प्राधिकारी को रिटर्न जमा करना होगा जिसमें उसे पूर्ववर्ती (1) के लिए वास्तविक सकल और शुद्ध टर्नओवर दिखाना होगा। वर्ष

और उस वर्ष के दौरान वास्तव में एकत्र किए गए कर या करों के माध्यम से रकम। फॉर्म ए में कॉलम 1 से 10 सकल टर्नओवर और सकल टर्नओवर से की जाने वाली कटौतियों से संबंधित हैं; कॉलम 10 में कर योग्य शुद्ध टर्नओवर दिखाया जाना आवश्यक है। कॉलम 11 में वास्तविक राशि को कर के माध्यम से एकत्रित की गई हो या धारा 8बी के तहत करों के अनुसार।”

हालाँकि सवाल अभी भी बना हुआ है - क्या उपरोक्त प्रावधान दो अधिनियमों की योजना के तहत ऐसा अंतर दिखाते हैं कि कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि डीलर के टर्नओवर का हिस्सा नहीं हो सकती है और यदि लागू अधिनियम इसे टर्नओवर का हिस्सा बनाता है एक घिनौने प्रावधान द्वारा, इसे राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से बाहर होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए? यहां इस बात पर जोर देना जरूरी है कि *कृष्णास्वामी मुदलियार* (11) के मामले में विधायी क्षमता का कोई सवाल ही नहीं उठता अपितु उक्त निर्णय केवल धारा 8बी और केवल टर्नओवर और मूल्यांकन नियम का निर्माण करता है।

हम नहीं सोचते कि *कृष्णास्वामी मुदलियार* citation के मामले में किया गया भेद केवल निर्माण के प्रश्न पर सही या गलत है, विधायी क्षमता के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। *टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी*

लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (12) मामले में इस न्यायालय ने बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 में मूल अधिनियमकी धारा 8बी के समान एक प्रावधान पर विचार किया। दास, मुख्य न्यायाधीश ने बहुमत की राय देते हुए कहा:

"संशोधन के बाद 1947 के अधिनियम ने विक्रेता को, जो एक पंजीकृत डीलर था, क्रेता से कर के रूप में बिक्री कर एकत्र करने की अनुमति दी, यह बिक्री कर का भुगतान करने के लिए विक्रेता की प्राथमिक देनदारी को समाप्त नहीं करता है। यह है इस तथ्य से यह और भी स्पष्ट हो गया है कि पंजीकृत व्यापारी को, यदि वह चाहे या चाहे तो, क्रेता से कर वसूलने की आवश्यकता नहीं है और कभी-कभी अन्य पंजीकृत व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण उसे अपना माल बेचना और अपना पुराना सामान रखना लाभदायक हो सकता है। ग्राहक बिक्री कर के बलिदान पर भी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बिक्री कर की आवश्यकता नहीं है। क्रेताओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और यह तथ्य कर की वास्तविक प्रकृति को नहीं बदलता है, जो कानून के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विक्रेता पर लगाया जाता है। खरीदार पर सहमत बिक्री मूल्य के अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व

नहीं है, जब तक कि अनुबंध में विशेष रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो। देखें *लव, बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स), लिमिटेड एलआर [1944] 1 केबी 484।*"

इन अवलोकनों से पता चलता है कि जब विक्रेता कर देता है और खरीदार कीमत के अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो कर वास्तव में संपूर्ण विचार का हिस्सा होता है और दो राशियों-कर और मूल्य-के बीच का अंतर सारा महत्व खो देता है। विधायी क्षमता का दृष्टिकोण. टर्नओवर और असेसमेंट नियमों के तहत यह मामला किसी भी तरह से अलग नहीं है। यह सच है कि फॉर्म ए के कॉलम 11 में धारा 8-बी के तहत कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि को दिखाना होगा; हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विधायी क्षमता की जड़ तक जाने वाला एक अपरिवर्तनीय अंतर तैयार किया गया है और इसे हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 8 बी एवं और टर्नओवर और मूल्यांकन नियम का वास्तविक प्रभाव यह है कि (ए) एक पंजीकृत डीलर कर को पार करने में सक्षम है, (बी) एक अपंजीकृत डीलर ऐसा नहीं कर सकता है, और (सी) कर के माध्यम से एकत्र की गई राशि दिखानी होगी अलग से, क्योंकि इसका भुगतान

सरकार को करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सूची 11 में प्रविष्टि 54 के अनुसार क्रेता द्वारा डीलर को भुगतान किए गए कर को बेचे गए माल के विचार में बिक्री मूल्य के साथ एक हिस्सा बनाने के लिए उपयुक्त प्रावधान द्वारा कानून बनाना विधायिका के लिए अक्षम है। डीलर का टर्नओवर; न ही इसका मतलब यह है कि कानून में सरकार द्वारा लगाया गया कर खरीदार पर लगने वाला कर है, जो डीलर को केवल संग्रहण एजेंसी बनाता है, ताकि कर हमेशा बिक्री मूल्य से बाहर रहे।

एक और पहलू है जिससे इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। हम मान लेंगे कि - मूल अधिनियम की योजना के तहत, कर द्वारा एकत्र की गई राशि और कर के अलावा बिक्री मूल्य के बीच एक अंतर निकाला जाता है। क्या इस तरह का भेद लागू अधिनियम द्वारा जारी और बरकरार रखा गया है? अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 2 की ओर आकर्षित किया है। आक्षेपित अधिनियम की धारा 2 में जहां अभिव्यक्ति "मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1939 के तहत कर के माध्यम से उसके द्वारा एकत्र किया गया" आता है। यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित अधिनियम में उपरोक्त अभिव्यक्ति को मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, धारा 2 मूल अधिनियम के तहत किए गए भेद को बनाए

रखता है और जारी रखता है। फिर, हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अभिव्यक्ति "कर आदि के माध्यम से उसके द्वारा एकत्र किया गया।" इस प्रकार एकत्र की गई "राशि" का केवल वर्णनात्मक है; धारा 2 की आवश्यक और क्रियाशील भाग में कहा गया है कि इस प्रकार एकत्र की गई रकम को डीलर के टर्नओवर का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए, व्यक्त शब्दों में धारा 2 में कहा गया है कि कर को टर्नओवर का हिस्सा माना जाएगा और सीमित अवधि के लिए 'टैक्स' और 'टर्नओवर' के बीच अंतर, यदि कोई हो, को मिटा दिया जाएगा, जिसके दौरान विवादित अधिनियम लागू होता है। धारा 2 के इस पहलू को *आंध्र सरकार बनाम ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड* (13) में विज्ञापित किया गया था। जहां आंध्र उच्च न्यायालय को कुछ अलग दृष्टिकोण से प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला, अर्थात्, मुख्य अधिनियम में अभिव्यक्ति 'टर्नओवर' की परिभाषा में आंध्र प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया गया एक संशोधन। संशोधित अधिनियम की धारा 2 में 'टर्न-ओवर' की निम्नलिखित परिभाषा प्रतिस्थापित की गई: -

"टर्नओवर का अर्थ है बिक्री के बिल में माल की बिक्री या खरीद के लिए प्रतिफल के रूप में निर्धारित कुल राशि (या यदि बिक्री का कोई बिल नहीं है, तो ली गई कुल राशि).. जिसमें किसी भी काम के लिए डीलर द्वारा ली गई कोई भी राशि शामिल है। माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले

बेचे गए माल के संबंध में और डीलर द्वारा ली गई कोई अन्य रकम, चाहे उसका विवरण, नाम या वस्तु कुछ भी हो।" शनशोधित अधिनियम की धारा 4 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 8 बी एवं 8 सी को प्रभाव शून्य कर दिया। इन संशोधनों के प्रभाव से निपटते हुए, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा,

"बिक्री कर की अंतिम आर्थिक घटना उपभोक्ता या अंतिम खरीदार पर होती है और वह माल के लिए जो भी भुगतान करता है वह केवल कीमत के रूप में भुगतान किया जाता है, यानी खरीद के लिए प्रतिफल के रूप में। वैधानिक दायित्व, हालांकि, के भुगतान के लिए बिक्री कर डीलर पर उसके कुल 'कारोबार' पर लगाया जाता है, भले ही उसे खरीददारों से कर की प्राप्ति होती हो या नहीं। आम तौर पर, डीलर द्वारा ली गई कीमत में बिक्री कर शामिल होगा, क्योंकि इसे पारित करना उसके हित में है। क्रेता पर कर का बोझ। जहां तक डीलर का संबंध है, बिक्री के अवसर पर प्योरबेसर द्वारा किए गए कर को कवर करने वाली राशि का भुगतान, वास्तव में उस कीमत का हिस्सा है जो क्रेता माल के लिए भुगतान करता है।"

बाद में, इसने श्री सुंदरराजन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य (14) मामले में निर्णय को मंजूरी के साथ संदर्भित किया। इस बाद के निर्णय में आक्षेपित अधिनियम की धारा 2 की वैधता पर सवाल उठाया गया और। उच्च न्यायालय ने कहा:

" धारा 2 में केवल यह अधिनियमित किया गया है कि ऐसी राशि को टर्नओवर का हिस्सा माना जाएगा और एक सीमित अवधि के लिए। अभिव्यक्ति के उपयोग का क्या प्रभाव होगा, इसके सुस्थापित सिद्धांत के लिए अधिकारियों को निर्धारित करना आवश्यक नहीं हो सकता है एक कानून में 'माना गया'। क्या विधायिका डीमिंग प्रावधान सहित धारा 2 को अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी, यह वास्तविक प्रश्न है। यदि विवादित अधिनियम की धारा 2 की वैधता स्थापित हो जाती है तो धारा 3 की वैधता को बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई होनी चाहिए, जिसने धारा 2 द्वारा अधिनियमित कानूनी कल्पना को प्रभावी बनाया।

जाहिर है, यह वह नाम नहीं है जिसे विधायिका एक क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान करने के लिए देती है, जो अधिनियम द्वारा परिभाषित एक डीलर है, जो विधायी

क्षमता के प्रश्न को निर्धारित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि धारा 8 बी में भुगतान को कर के रूप में (एकत्रित) राशि कहा गया है। यह भी उतना ही सच है कि बिक्री कर का भुगतान करने का वैधानिक दायित्व डीलर पर होता है। कर योग्य बिक्री का प्रत्येक लेनदेन नहीं बल्कि डीलर का कुल कारोबार है, जिसकी गणना अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। लेकिन यह सर्वविदित है कि वैधानिक प्रावधानों का जो भी रूप हो, कर का अंतिम आर्थिक प्रभाव उपभोक्ता, क्रेता पर पड़ता है। यह वह सुस्थापित सिद्धांत था जिसे *बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य* (15) मामले में पुनः कहा गया था। भले ही पंजीकृत डीलर अधिनियम की धारा 8 बी के अधिकार के तहत कर के माध्यम से राशि एकत्र करता है, डीलर द्वारा बिक्री के अवसर पर भुगतान क्रेता द्वारा किया जाता है। डीलर की तुलना में यह वास्तव में उस कीमत का हिस्सा है जो क्रेता को सामान खरीदने के लिए विक्रेता को भुगतान करना पड़ता है। इस तरह के भुगतान पर कर, हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 246(3) के साथ पढ़ी जाने वाली सूची 11, अनुसूची VII की प्रविष्टि 54 के दायरे में है। "

हमारा विचार है कि उपरोक्त अवलोकन सही ढंग से धारा 2 को प्रभाव देते हैं। आक्षेपित अधिनियम की धारा 3 केवल परिणामी है।

श्री सीकरी जो की महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों की ओर से पैरवी कर रहे हैं ने हमारा ध्यान कुछ अमेरिकी निर्णयों की ओर आकर्षित किया है जो दिखाते हैं कि ऐसे मामलों में जहां कर खरीदार को दिया जाता है, कर को बिक्री मूल्य का हिस्सा मानना अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और कानून के लिए अज्ञात नहीं है (देखें *लैश उत्पाद कंपनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 73 एल संस्करण 251; प्योर तेल कंपनी बनाम अलबामा राज्य, 148 अमेरिकी कानून रिपोर्ट 260*)। हम इन निर्णयों की जांच करना अनावश्यक मानते हैं, क्योंकि लागू अधिनियम की वैधता मूल अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अपनी शर्तों पर निर्धारित की जानी चाहिए। मूल अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में आक्षेपित अधिनियम को पढ़ने पर, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आक्षेपित अधिनियम को विधायी अक्षमता के आधार पर खराब नहीं ठहराया जा सकता है। टर्नओवर की परिभाषा के तहत कुल राशि जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है, कर योग्य है। इस कुल राशि में खरीदार द्वारा भुगतान की गई कीमत के हिस्से के रूप में कर शामिल है। जब तक डीलर कर का भुगतान नहीं करता तब तक यह राशि डीलर के सामान्य खाते में चली जाती है। यह वह धन है जिसे वह अपने व्यवसाय के लिए तब तक उपयोग करता रहता है

जब तक वह इसे सरकार को भुगतान नहीं कर देता। दरअसल, वह इसे तब तक बार-बार पलट सकता है जब तक कि वह अंततः इसे सरकार को सौंप न दे। इस प्रकार कानून में इसे उस राशि का हिस्सा मानने में कोई विसंगति नहीं है जिस पर उसे कर का भुगतान करना होगा। टर्नओवर की यह अवधारणा नई नहीं है। यह इंग्लैंड और अमेरिका में पाया जाता है और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि जब भारत में विधानमंडलों ने कर को भी शामिल करने के लिए 'टर्नओवर' को परिभाषित किया, तो वे कुछ अज्ञात और पहले से अनसुनी बात पर प्रहार कर रहे थे।

इन अपीलों में जो एकमात्र प्रश्न उठाया गया है वह विवादित अधिनियम की वैधता के संबंध में है। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय होने के कारण, अपीलें विफल हो जाती हैं और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती हैं। एक सुनवाई शुल्क।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंशुमान सिंह खंगारोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।